[Shri Palvai Govardhan Reddy]

the oil palm farmers. It is all happening due to reduction in the duty from 80 per cent in 2005 to zero per cent now. The total import of edible oils during 2011-12 has already reached 8.5 million tonnes.

Now, palm oil mills are purchasing one tonne Fresh Fruit Bunches for Rs.5,730. In May, it was Rs.7,800. The CACP recommended for giving Rs.8,500, but it has not been implemented. So, if free imports are allowed, oil palm farmers will be ruined. Hence, I request the Government of India to intervene in this immediately and impose import duty on palm oil and ensure implementation of CACP recommendation.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: I associate myself with the Special Mention made by Shri Palvai Govardhan Reddy.

Demand to withdraw the provision of making English Language a mandatory paper in Civil Services Examination held by UPSC

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (उत्तर प्रदेश) : महोदय, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की परीक्षा के ढांचे में परिवर्तन करके अंग्रेजी जानने वाले छात्रों का दबदबा कायम करवा दिया है। इससे ग्रामीण इलाकों के पिछड़े एवं दलित आदिवासियों के छात्रों का नुकसान होगा, क्योंकि इनकी पढ़ाई-लिखाई अंग्रेजी वातावरण में नहीं होती। नये ढांचे में अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य कर दिया है, जबकि पहले अंग्रेजी अथवा भारतीय भाषाओं का एक प्रश्न-पत्र होता था। पहले भाषा के पेपर में केवल पास होना अनिवार्य था, उसके नम्बर फाइनल की मैरिट में नहीं जुड़ते थे। सर, यह पूरे देश की क्लास वन परीक्षा का सवाल है। अब अंग्रेजी पेपर के नम्बर प्रिलिम्स एवं मेन परीक्षाओं के आधार पर तैयार की जाने वाली सूची का हिस्सा बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जिन छात्रों की अंग्रेजी कमजोर है, उनके लिए अब सिविल सर्विस की परीक्षा में चयनित होना आसान नहीं होगा। पुरानी पद्धति में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर परीक्षा पास करने वाले छात्रों में देहात के गरीब, हर वर्ग के पिछड़े, दलित, आदिवासी छात्रों की संख्या अधिक थी। उदाहरण के लिए पिछले पांच वर्षों में गुजरात में 85 छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा पास की, उनमें से कम से कम 50 छात्रों ने गुजराती साहित्य की मुख्य पेपर बनाया। अब भारतीय भाषाओं जैसे - तमिल, तेलगु, कन्नड़, गुजराती, मलयाली, बंगला, असमी आदि भाषाओं को मुख्य पेपर में रखने की सुविधा नहीं होगी जबकि अंग्रेजी अनिवार्य होगी। इसका परिणाम यह होगा कि अभिजात्य वर्ग और आम आदमी के बच्चे के लिए यूपीएससी के चयन में भाषा एक दीवार बनकर खड़ी

होगी और अधिकारियों के व्यवहार में अंग्रेजियत दिखाई पड़ेगी। असली भारत को समझने, जानने वाले देहाती बच्चों, विशेषकर पिछड़े, दलित, मुस्लिम आदिवासी अधिकारी कम बनेंगे।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि पुरानी परीक्षा प्रणाली लागू करे और अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करके भारतीय भाषाओं को इसमें रखे, ताकि गांव के हर वर्ग के, उच्च वर्ग के गरीब बच्चे तथा पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुस्लिम बच्चे चयनित हो सकें। धन्यवाद।

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

चौधरी मुनब्बर सलीम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

†[ ]**چودھری منوّر سلیم (اتر پردیش):** مہودے، میں اپنے آپ کو اس سے سمبدّھ کرتا ہوں۔ [ ]

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): I associate myself with the Special Mention made by Prof. Baghel.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): I associate myself with the Special Mention made by Prof. Baghel.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): I associate myself with the Special Mention made by Prof. Baghel.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Andhra Pradesh): I associate myself with the Special Mention made by Prof. Baghel.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The whole House associates itself with the Special Mention made by Prof. Baghel.

Demand to take effective steps to resolve the problems being faced by fishermen in the country

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : महोदय, "राष्ट्रीय फिश वर्कर फोरम" और "महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समिति" की तरफ से दिनांक 4 मार्च, 2013 से जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है। फोरम की तरफ से मछुआरों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

देश के सागर का किनारा 8129 किलोमीटर है। यह किनारा गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि दस राज्यों से लगा हुआ है। इस किनारे पर सदियों से सागर से मछलियां पकड़ने का कार्य किया जा रहा है।

---

†[ ]Transliteration in Urdu Script.